

दिलीप घोष ने कहा सरकार बनी तो बंगाल में भी होगी एनआरसी



कोलकाता।

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दूसरा ड्राफ्ट आने पर अभी सियासत थमी भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भी इसी तर्ज नागरिकों की पहचान कराने की बात कही है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार आती है असम की तरह ही बंगाल में भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जारी किया जाएगा। असम में एनआरसी के सम्पूर्ण मसौदे को जारी करने के समर्थन में उन्होंने कहा कि कुछ नेता 'घड़ियाली आंसू' बहा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी 'वोट बैंक' की राजनीति के खत्म होने का अंदेशा है। असम में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का अंतिम मसौदा सोमवार को जारी कर दिया गया। असम देश में एक मात्र ऐसा राज्य है जहां एनआरसी जारी किया गया है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य के कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम हैं। जबकि करीब 40 लाख लोग अवैध पाए गए हैं।

अवैध नागरिकों को भेजेगे बांग्लादेश: दिलीप घोष ने कहा, 'अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है तो हमलोग राज्य में भी एनआरसी लागू करेंगे। हमलोग अवैध नागरिकों को बांग्लादेश वापस भेजेंगे।

ई-कॉमर्स कंपनियों को भारत में रखना होगा डेटा

नई दिल्ली। पिलपकार्ट जैसी ई कॉमर्स और सोशल मीडिया कंपनियों को अपने यूजर्स के डेटा को भारत में ही रखना पड़ सकता है। ई-कॉमर्स के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे में यह कहा गया है। सरकार कंपनी कानून में भी संशोधन विचार कर सकती है ताकि ई-कॉमर्स कंपनियों में संस्थापकों की हिस्सेदारी घटने के बावजूद उनका नियंत्रण बना रह सके। मसौदा नीति के मुताबिक जिन आंकड़ों को भारत में ही रखने की आवश्यकता होगी।

एसबीआई ने खास अवधि की एफडी पर बढ़ाई ब्याज दरें

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने सोमवार को कुछ खास अवधि की सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) पर ब्याज दरों में बढ़ि का ऐलान किया है। ब्याज दरें 5 से 10 बैसिस पॉइंट्स यानी 0.05% से 0.1% तक बढ़ाई गई हैं। नई दरें सोमवार, 30 जुलाई से ही लागू हो चुकी हैं। एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि वह 1 से 2 साल की एफडी पर अब 6.70% की दर से ब्याज देगा जो से पहले 6.65% था। वहीं, 2 से 3 वर्ष की एफडी पर ब्याज दर 6.65% से बढ़ाकर 6.75% कर दी गई है।

अस्पताल ने जारी किया था मेडिकल बुलेटिन

रविवार की रात अस्पताल की ओर से रात दस बजे जारी मेडिकल बुलेटिन में करुणानिधि की तबीयत में सुधार के संकेत दिए गए हैं। हालांकि, इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने कोयंबटूर में सोमवार को होने वाली बैठक को रद्द कर दिया था और वह चेन्नई के लिए लौट गए। वहीं पुलिस द्वारा की गई अपील के बावजूद समर्थक अस्पताल के बाहर डटे रहे। अव्यवस्था फैलती देख पुलिस को डीएमके समर्थकों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा।

जर्जर दीवार गिरी एक बच्चे की मौत, बहन घायल

नई दिल्ली। थाना सागरपुर इलाके में एक मकान की दीवार गिर गई। जिसकी चपेट में आकर दीवार के पास खेल रहे भाई-बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रविवार करीब साढ़े ग्यारह बजे की है, जिसका पता चलने के बाद बच्चों के परिजनों ने अन्य लोगों के सहयोग से दोनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने लड़के को मृत घोषित कर दिया। जबकि उसकी बहन का गंभीर अवस्था में इलाज किया जा रहा है। मृत बच्चे की पहचान 12 वर्षीय रोहित के रूप में हुई है।

घायल बच्ची की पहचान 10 वर्षीय रीटा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मजदूरी करने वाले चन्द्रशेखर (38) परिवार के साथ सागरपुर इलाके में किराए के मकान में रहते हैं। करीब साढ़े ग्यारह बजे चन्द्रशेखर का बेटा रोहित व बेटा रीटा घर के बाहर खेल रहे थे। तभी अचानक से रोहित ने पास की दीवार को जैसे ही हाथ लगाया, पूरी की पूरी दीवार गिर पड़ी।

दैनिक क्रांति समय

असम में 40 लाख लोग अवैध नागरिक

असम इकलौता राज्य जहां नेशनल रजिस्टर बन रहा, रजिस्टर के विरोध में प्रदर्शन की आशंका, सात जिलों में धारा 144 लागू

राजनीतिक बवाल

● नागरिकता के लिए 3,29,91,380 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2,89,38, 677 को नागरिकता के लिए योग्य पाया गया

नई दिल्ली। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन का फाइनल ड्राफ्ट जारी होने के साथ ही राजनीतिक बवाल भी शुरू हो गया है। इस ड्राफ्ट में 40 लाख लोगों के नाम नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों का क्या होगा? 40 लाख लोगों के नाम रजिस्टर में क्यों नहीं हैं, इसके कारणों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि चार श्रेणियां जरूर बताई गई हैं, जिनसे जुड़े लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए। वह है, डी (संदेहास्पद) वोटर्स, डी, वोटर्स के बच्चे व परिवार के लोग, जिनके मामले विदेशी न्यायाधिकरण में लंबित हैं और उनके बच्चे। हालांकि, यह फाइनल लिस्ट नहीं है बल्कि ड्राफ्ट है। जिन लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं हैं, वे इसके लिए दावा कर सकते हैं। असम में तनाव है और संसद में मामला सोमवार को उठा तो केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सरकार की तरफ से पक्ष रखना पड़ा।

40 लाख लोगों का क्या होगा?

नागरिकता के लिए 3,29,91,380 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2,89,38, 677 को नागरिकता के लिए योग्य पाया गया है। जिन 40 लाख लोगों का नाम लिस्ट से बाहर है उनके पास अभी भी क्लेम करने का दूसरा अवसर है।

एनआरसी को ऑर्डिनेटर ने कहा था कि इस लिस्ट के आधार पर किसी भी नागरिक को फिलहाल डिटेन्शन सेंटर में नहीं भेजा जाएगा।



व्या है नैशनल रजिस्टर? नए नेशनल सिटिजन रजिस्टर में असम में बसे सभी भारतीय नागरिकों के नाम, पते और फोटो हैं। यह पहला मौका है, जब सूबे में अवैध रूप से रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। देश में लागू नागरिकता कानून से थोड़ा अलग रूप में राज्य में असम अर्कोर्ड, 1985 लागू है। इसके मुताबिक 24 मार्च, 1971 की आधी रात तक सूबे में प्रवेश करने वाले लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा।

लिफ योग्य पाया गया है। जिन 40 लाख लोगों का नाम लिस्ट से बाहर है उनके पास अभी भी क्लेम करने का दूसरा अवसर है।

एनसीआर में नाम के लिए कैसे कर पाएंगे दावा:

अब यह भी सवाल सामने आ रहा है कि अंतिम ड्राफ्ट आने के बाद जिनका नाम एनआरसी में नहीं आता है उनका भविष्य क्या होगा? एनआरसी लिस्ट को लेकर उलझन और संशय पर राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, 'इस मामले में पूरी

शिमला। एनसीसी राष्ट्र के युवाओं में चरित्र, अनुशासन, नेतृत्व, साहस की भावना तथा निस्वार्थ सेवा के आदर्शों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह अतिरिक्त महानिदेशक एनसीसी मुख्यालय, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल आर.एस. मान (वीएसएम), (जिन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री से मुलाकात की) से मुलाकात के



आपके पास वलम करने का एक और मौका है। आप 30 अगस्त से 28 सितंबर तक दावा कर सकते हैं। असम में मौजूद आवेदक हेल्पलाइन नंबर 15107 पर किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। असम के बाहर के आवेदक 18003453762 नंबर पर कॉल कर जानकारी दे सकते हैं। रजिस्टर में उन्हीं लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे, जो खुद

पारदर्शिता बरती जाएगी। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि इसमें केंद्र का क्या रोल है? यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के नियामनी में चल रहा है। इस तरह के संवेदनशील मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो ड्राफ्ट आया है, वह अंतिम नहीं है। इसके बाद भी दावा किया जा सकता है। जिन्हें लगता है कि

एनसीसी शिक्षकों की होगी तैनाती

● मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए एनसीसी के सहयोग का किया आह्वान

शिमला। एनसीसी राष्ट्र के युवाओं में चरित्र, अनुशासन, नेतृत्व, साहस की भावना तथा निस्वार्थ सेवा के आदर्शों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह अतिरिक्त महानिदेशक एनसीसी मुख्यालय, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल आर.एस. मान (वीएसएम), (जिन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री से मुलाकात की) से मुलाकात के

महिलाओं का जीवन सिर्फ शादी के लिए नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में प्रचलित नाबालिग लड़कियों का खतना किए जाने की प्रथा पर सवाल उठाए हैं। सोमवार को खतने के विरोध में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं का खतना सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता कि उन्हें शादी करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं का जीवन केवल शादी और पति के लिए नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट से महिलाओं का खतना किए जाने की प्रथा पर भारत में पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की गई है। सोमवार को कोर्ट ने कहा कि शादी के अलावा भी महिलाओं का

दौरान कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि एनसीसी के कैडेटों ने समाज की निःस्वार्थ सेवा और स्वयं सहायता के महत्व को समझते हुए पर्यावरण की रक्षा करने और समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों का उत्थान करने के उद्देश्य से सामुदायिक विकास गतिविधियों को अपनाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में 23

हजार से अधिक एनसीसी कैडेट अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नेन्द्र मोदी देश में एनसीसी की गतिविधियों के विस्तार व सुदृढ़ करने पर विशेष बल दे रहे हैं। वर्तमान में देश में 16 लाख एनसीसी कैडेट हैं तथा उनकी संख्या को 19 लाख करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कि प्रमोद जयसिंह होरे ने रविवार को फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिखा था कि वह आरक्षण की मांग के समर्थन में अपनी जान दे देगा। उसने रविवार रात यहाँ कुंठवाड़ी क्षेत्र में चलती ट्रेन के सामने कथित रूप से छलांग लगा दी। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, जयसिंह ने फेसबुक पर लिखा था, 'आज एक मराठा छोड़कर जा रहा है.....लेकिन मराठा आरक्षण के लिए कुछ कीजिए' मराठा लोक सेवा

आयोग की परीक्षा की तैयारी में जुटे जयसिंह ने एक अन्य संदेश में लिखा था, 'मराठा आरक्षण एक जान लेगा। उसके कई दोस्तों ने उससे ऐसा नहीं करने का अनुरोध किया।

शिवसेना ने फड़नवीस से कहा विशेष सत्र बुलाएं

महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन हिंसक देख शिवसेना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस से तुरंत विशेष सत्र बुलाने के लिए कहा है।

मेहुल चोकसी को एंटिगा 'एनसीसी शिक्षकों की होगी तैनाती' में ही घेरने की तैयारी

नई दिल्ली। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के मुद्दे पर भारत के उच्चायुक्त ने एंटिगा और बारबुडा के संबंधित सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, उच्चायुक्त ने एंटिगा और बारबुडा के अधिकारियों को लिखित और मौखिक तौर पर वहाँ चोकसी की मौजूदगी की पुष्टि करने, उसे हिरासत में लेने और जल, वल अथवा

वायु, किसी भी मार्ग से उसकी आवाजाही पर पाबंदी लगाने को कहा। भारत में सरकारी सूत्रों ने बताया कि हमारे उच्चायुक्त एंटिगा और बारबुडा सरकार के उपयुक्त अधिकारियों से मिल रहे हैं। हम भारत एवं एंटिगा-बारबुडा की सरकारों की उपयुक्त एजेंसियों के साथ तालमेल बिटाने की कोशिश में जुटे हैं और हमने मामले पर लगातार नजर बना रखी है। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक फ्राँड केस में सलिलत रहा है।

10 साल का मेगा प्लान, भारत में ही बनेंगे फाइटर प्लेन

नई दिल्ली ■ एजेंसी

केंद्र सरकार अगले महीने एक प्रमुख नीति सार्वजनिक कर बड़ा रक्षा उत्पादन उद्योग बनाने और भारत को अगले 10 साल में सैन्य उपकरणों के शीर्ष पांच निर्माताओं में शामिल करने का खाका पेश करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि रक्षा उत्पादन नीति (डीपीपी-2018) का प्रमुख जोर लड़ाकू विमानों, लड़ाकू हेलीकॉप्टरों और स्वदेशी हथियारों सहित अत्याधुनिक सैन्य प्लैटफॉर्मों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने की खातिर पर्याप्त संसाधनों में निवेश पर होगा। सूत्रों ने बताया कि डीपीपी-2018 अगले महीने जारी किए जाने की संभावना है। नीति के मसौदे के मुताबिक, सरकार वर्ष 2025 तक सैन्य वस्तुओं एवं सेवाओं में 1,70,000 करोड़ रुपये के कारोबार को हासिल करने के बारे में सोच रही है। स्वीडन के एक थिंक टैंक ने मार्च में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पिछले पांच साल में भारत दुनिया में सैन्य हार्डवेयर का सबसे बड़ा आयातक रहा है। वर्ष 2004-08 की तुलना में भारत द्वारा पिछले पांच साल में प्रमुख हथियारों के आयात में 111 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

नई दिल्ली (एजेंसी)।

महाराष्ट्र के पुणे जिले मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आगे के हवाले कर दिया है और रास्तों पर चक्का जाम कर दिया है। हंगामा बढ़ते देख शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल, मराठा आरक्षण आंदोलन के तहत पुणे के नजदीक चाकण में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शन के बाद ही चाकण में आंदोलन अचानक

हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने रोड जाम कर दिए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पाने की पूरी कोशिश की लेकिन हालात बेकाबू होते देख उन्हें आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को गाड़ियों को भी निशाना बनाया है। आंदोलन के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की बैठक के बाद राज्यपाल विद्यासागर राव को ज्ञापन सौंपा

और कहा कि वह मराठा आरक्षण मामले में हस्तक्षेप करें। कांग्रेस ने मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने की मांग की।

आरक्षण की मांग को लेकर व्य्क्ति ने की आत्महत्या

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ 35 साल के एक व्यक्ति ने चलती ट्रेन के सामने छलांग लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। मुकुंदवाड़ी थाने के वरिष्ठ निरीक्षक नाथा जाधव ने बताया

बंगाली लोगों को भगा रही है बीजेपी सरकार: ममता



कोलकाता। असम में रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) का दूसरा और आखिरी ड्राफ्ट पेश कर दिया गया है। इसके तहत 2 करोड़ 89 लाख 83 हजार 677 लोगों को वैध नागरिक मान लिया गया है। इस तरह से करीब 40 लाख लोग अवैध पाए गए हैं। ड्राफ्ट के आते ही सियासत तेज हो गई है। टीएमसी ने जहाँ असम में एनआरसी ड्राफ्ट के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। वहीं टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एनआरसी के नाम पर बंगाली लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने असम एनआरसी पर कहा कि कई लोगों के पास आधार कार्ड और पासपोर्ट होने के बावजूद उनका नाम ड्राफ्ट में नहीं है। सही दस्तावेजों के बावजूद लोगों को ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया। उन्हें सरनेम की वजह से बाहर किया गया है। क्या बीजेपी सरकार जबरदस्ती लोगों को बाहर निकालना चाहती है? केंद्र बंगाली लोगों को निशाना बना रही है और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ममता ने चिंता जताते हुए कहा कि 40 लाख लोग जिन्हें ड्राफ्ट से बाहर किया गया है, वो कहां जाएंगे?।

'महिलाओं का जीवन सिर्फ शादी के लिए नहीं'



उठे सवाल

● महिलाओं का खतना सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता कि उन्हें शादी करनी है: सुप्रीम कोर्ट

दायित्व है। इस तरह की प्रथा महिलाओं की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लैंगिक संवेदनशीलता का मामला है और स्वास्थ्य ने लिए खतरनाक भी हो सकता है।

बुलेट ट्रेन में महिला-पुरुष के लिए होंगे अलग शौचालय, बेबी चेंजिंग रूम की भी होगी सुविधा

नई दिल्ली। आगामी मुंबई-अहमदाबाद उच्च-गति रेल गलियारा परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण में देरी से इसके लांच की तारीख को आगे खिसकाना पड़ सकता है, लेकिन रेलवे बुलेट ट्रेन के विभिन्न कल-पुरजों और यात्रियों की सुविधाओं को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बुलेट ट्रेन में यात्रियों को बाल पोषण के लिए अलग से कमरा मुहैया कराया जाएगा। बीमार लोगों के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी और पुरुष व महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए जाएंगे। भारतीय रेलवे में ये सुविधाएं पहली बार प्रदान की जाएगी। सभी ट्रेनों में 55 सीटें बिजनेस क्लास और 695 सीटें स्टैंडर्ड क्लास के लिए आरक्षित होंगी। ट्रेन में यात्रियों को सामान रखने के लिए जगह दी जाएगी। ईड शिकनसेन सिरिज बुलेट ट्रेन में बेबी चेंजिंग रूम की भी सुविधा दी जाएगी, जिसमें बेबी टॉयलेट सीट, डायपर डिस्पोजल और बच्चों के हाथ धोने के लिए कम ऊंचाई के सिंक लगे होंगे। व्हीलचेयर वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त जगह वाले टॉयलेट की सुविधा दी जाएगी। रेलवे द्वारा बुलेट ट्रेन के लिए तैयार अंतिम रूपरेखा के अनुसार, 150 सीटों वाले ईड शिकनसेन एक नए जमाने का हाई स्पीड ट्रेन है। इसमें वाल लामाटेंड टाईप यूरेनल की सुविधा प्रदान की जाएगी। डिब्बों में आरामदायक खवालित घूमने वाली सीट प्रणाली होगी। ट्रेन में फीजर, हॉट केस, पानी उबालने की सुविधा, चाय और कॉफी बनाने की मशीन और बिजनेस क्लास में हैंड टॉवल वार्मर की सुविधा प्रदान की जाएगी। डिब्बों में एलसीडी स्क्रीन लगी होगी, जहां मौजूदा स्टेशन, आने वाले स्टेशन, गंतव्य और अगले स्टेशन पहुंचने और गंतव्य पहुंचने के समय के बारे में जानकारी आती रहेगी।

मराठा आंदोलन हुआ हिंसक, शिवसेना ने देवेंद्र फड़नवीस से कहा विशेष सत्र बुलाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पुणे जिले मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आगे के हवाले कर दिया है और रास्तों पर चक्का जाम कर दिया है। हंगामा बढ़ते देख शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल, मराठा आरक्षण आंदोलन के तहत पुणे के नजदीक चाकण में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शन के बाद ही चाकण में आंदोलन अचानक

हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने रोड जाम कर दिए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पाने की पूरी कोशिश की लेकिन हालात बेकाबू होते देख उन्हें आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को गाड़ियों को भी निशाना बनाया है। आंदोलन के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की बैठक के बाद राज्यपाल विद्यासागर राव को ज्ञापन सौंपा

और कहा कि वह मराठा आरक्षण मामले में हस्तक्षेप करें। कांग्रेस ने मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने की मांग की।

आरक्षण की मांग को लेकर व्य्क्ति ने की आत्महत्या

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ 35 साल के एक व्यक्ति ने चलती ट्रेन के सामने छलांग लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। मुकुंदवाड़ी थाने के वरिष्ठ निरीक्षक नाथा जाधव ने बताया

आयोग की परीक्षा की तैयारी में जुटे जयसिंह ने एक अन्य संदेश में लिखा था, 'मराठा आरक्षण एक जान लेगा। उसके कई दोस्तों ने उससे ऐसा नहीं करने का अनुरोध किया।

शिवसेना ने फड़नवीस से कहा विशेष सत्र बुलाएं

महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन हिंसक देख शिवसेना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस से तुरंत विशेष सत्र बुलाने के लिए कहा है।

काल सब प्राणियों के सिर पर है, इसलिए पहले कुशलक्षेम पूछना चाहिए -कालिदास

सामाजिक सुरक्षा विधेयक

सरकार द्वारा सबको मुफ्त चिकित्सा, पेंशन और बेरोजगारी भत्ता दिलाने वाले सामाजिक सुरक्षा विधेयक को संसद के इसी सत्र में पारित कराने की कोशिश आकर्षित करती है। सरकार विपक्षी दलों को मनाने के लिए प्रयासरत है कि इस विधेयक को समर्थन दे दें। विधेयक का जो प्रारूप सामने आया है, उसके अनुसार इसके तहत देश के प्रत्येक नागरिक चाहे वो अमीर हों या गरीब सभी का निबंधन किया जाएगा। इसमें कई अन्य योजनाओं की तरह उम्र का भी कोई बंधन नहीं होगा। इसमें यदि निर्बंधित व्यक्ति की नौकरी छूट गई तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। प्रश्न है कि इसके लिए धन कहाँ से आएगा ? इसके उत्तर में कहा गया है कि धन की व्यवस्था केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के जरिए की जाएगी। पता नहीं इसमें किसनी सफलता मिलेगी, क्योंकि अभी तक ऐसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के किसी ढांचे का देश को अनुभव है ही नहीं। किंतु इसका विरोध भी हो रहा है। विरोधी दलों को लगता है कि सरकार 2019 चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ उठा लेगी। इसलिए वो इस पर कई प्रश्न उठा रहे हैं। इसी तरह सरकार ने इस पर एकराय बनाने के लिए श्रमिक संगठनों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कई संगठनों ने भाग ही नहीं लिया। ये भी कई प्रश्न उठा रहे हैं। मसलन, सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए धन कहाँ से आएगा ? दूसरे, नये कानून आने के साथ 15 पुराने कानून समाप्त हो जाएंगे और कार्य करते समय चोट और मृत्यु होने पर मुआवजा नहीं मिलेगा। भविष्य निधि और ईएसआई जैसी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। हालांकि अगर ऐसी कोई व्यापक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था हो जाए तो बहुत सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और वो सब इनमें समाहित हो जाएंगे। हमारा मानना है कि इस पर राजनीतिक नजरिए से हटकर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा सामाजिक सुरक्षा ढांचा, जिससे कोई नागरिक बाहर रहे ही नहीं, बड़ा संकल्प है। इसमें समस्याएं होंगी। बावजूद इसके इसे कानून का रूप दिलाने में देश को एक होना चाहिए। धनपतियों का निबंधन अवश्य होगा लेकिन वे अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे। इसी तरह जो नौकरी करते होंगे उनका खर्च नियोक्ता वहन करेगा। हां, जो गरीबों का खर्च केंद्र और राज्य सरकार वहन करेगी। भविष्य निधि तथा ईएसआई खत्म करने की बात इसमें नहीं है। कोई सरकार पूरा विकल्प दिए बगैर इसे खत्म नहीं कर सकती।

अलगाववादी रवैय

पार्टी (पीडीपी) पुराने एजेंडे पर लौटती दिख रही है। एक तरफ पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अलगाववादी राज आलाप रही है तो वहीं उनकी पार्टी का सांसद देश बंटवारे की धमकी दे रहा है। दल के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर महबूबा ने अनुच्छेद 35–ए को बचाने की अपील राज्य के सभी दलों के अलावा अलगाववादी गुटों से की है। महबूबा ने कहा कि अनुच्छेद 35–ए राज्य के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसे बचाने के लिए मुख्यधारा के सभी राजनीतिक दल और अलगाववादी मतभेद भुलाकर साथ आएं। साफ तौर पर महबूबा अब सत्ता का सुख भोगने के बाद एक बार फिर से जहर उगलने के खेल में लग गई हैं। अनुच्छेद 35–ए को बचाने के बास्ते देश विभाजक गुटों को भी एक प्लेटफार्म पर आने की गुहार लगाना यही परिलक्षित करता है कि कश्मीर का मसला केंद्र सरकार के लिए सुलझाना उतना आसान नहीं है, जितना दावा सरकार और सेना करती रही है। खासकर जब किसी राज्य की मुख्यमंत्री और उनका दल अलगाववादी रवैये के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। यह देश के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। इससे पहले ही देश की अखंडता पर जम्मू-कश्मीर के नेता और सियासी दल हमला करते रहे हैं। बात यहीं तक रहे तो भी गनीमत है। पीडीपी के 19वें स्थापना दिवस समारोह में जहर भरी बातें उनके एक सांसद ने भी की। मुजफ्फर हुसैन बेग ने गोरक्षा के नाम पर देश के बंटवारे की धमकी तक दे डाली।

देश की गंगा-जमुनी तहजीब की अनदेखा करते हुए बेग ने केंद्र सरकार को धमकाते हुए कहा कि अगर गोरक्षा के नाम पर मुसलमानों को मारना बंद नहीं हुआ तो देश का बंटवारा तय है। क्या ऐसे बकाने देने वालों और देश की एकता पर हमला करने वालों के साथ किसी तरह की मुरव्वत की जानी चाहिए ? दरअसल, सारा खेल सत्ता की मलाई खाने का है। हमेशा से पत्थरबाजों, देशविरोधी ताकतों के साथ गलबहियां करने वालों को देश की संप्रभुता रास नहीं आई है। सरकार को ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लेना होगा। कोशिश होनी चाहिए कि आतंकवाद पर मुलायम रख अपनाने और राज्य व देश में अमन बहाली की राह में रोड़ा अटकाने वालों पर सख्ती हो। ऐसे लोग न केवल देश बल्कि कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत के लिए बड़ा खतरा हैं।

सत्संग

अहिंसा व्रत का पालन

पशु-पक्षी तुल्य मात्रा अपने तक ही सीमित न रहे अपितु दूसरों के भी काम आए, किसी का दुख-दर्द समझे। किसी भी प्रकार से किसी को दुख या कष्ट न पहुंचाए। जो सुखाभिमानी दूसरों को दुख में देखकर प्रसन्न होता है, उसे एक दिन स्वयं भी दुखी होना पड़ता है। प्रभु प्रेम में आंसू बरसाने वाले को दुख के आंसू नहीं बरसाने पड़ते। जीवों पर करु णा व दया बरसाएं। पूर्ण रूपेण अहिंसा व्रत का पालन करें। बहिर्मुखता त्यागकर अंतर्मुख होंगे तो भक्तिपथ पर आगे बढ़ते हुए परमात्मा का साक्षात्कार कर सकेंगे। अभ्यास के द्वारा मन की चंचलता को रोकें। मन, परमात्मा की अमानत है। इसे परमात्मा में ही लगाएं। इसे विषय भोग, संसार, सांसारिकता, भोग-विलासों में लगाने पर अंततः दुखी होना पड़ेगा। छोटी-छोटी बातों से अपने प्रेम, एकता व सद्भाव को समाप्त न करें। श्रद्धा व विास से ही अंत:करण में स्थित ईर को देख सकते हैं। हनुमान की भांति मान का हनन करके भक्तिपथ की ओर अग्रसर हों। अभिमान प्रभु-प्राप्ति में प्रमुख बाधक है। अभिमान चाहे रूप, धन, वैभव, तप, ज्ञान इत्यादि किसी प्रकार का क्यों न हो-ठीक नहीं होता है। मानव के जीवन पर संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, इसलिए अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा विचारो, अच्छा संग करो। खान-पान व जीवन को सात्विक शुद्ध और संयमित बनाओ। खान-पान का मन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। प्रकृति के नियमों का पालन करो। शांति को जीवन में प्रमुखता से स्थान दो। अशांत व्यक्ति को कहीं भी सुख नहीं मिलता। सत्य परमात्मा का स्वरूप है। सत्य जहां भी जुड़ेगा, वहां विकृति नहीं आएगी। जिस सत्यपुरुष, सत्वचन, सद्ब्यवहार, सद्आचरण, सद्भाव इत्यादि का संग मिले, उसका जीवन धन्य है। जिसके जीवन में करुणा, क्षमा, उदारता, कोमलता, सेवा, परोपकार, परमार्थ है, वहीं संत है। संत वेशभूषा या बाहरी दिखावे से नहीं, संतता से है। परमात्मा अप्राप्त नहीं, नित्य प्राप्त हैं। मात्रा प्राप्ति की स्मृति व जागृति के लिए निरंतर सत्संग के प्रकाश में जीना है। जीना ही एक कला है। जीना उसी का है, जिसका जीवन उत्थान की ओर है। गिरना व गिराना बहुत सरल है परंतु उठना व उठाना उतना सरल नहीं है, किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। स्वयं जागो व औरों को जगाओ, अपने कल्याण के साथ औरों के कल्याण के भी भागीदार बनो। उठो! जागो!

कानून के क्रियान्वयन में आने से इसइल में रह रहे अन्य धर्म के लाखों निवासियों के साथ बड़े स्तर पर धार्मिक भेदभाव की आशंका चिंता का मूल कारण है। 120 सदस्यीय संसद में ``यहूदी राष्ट्र बिल’ पर हुए मतदान में शामिल 62 सांसदों में 55 सांसदों की सहमति के बाद पारित इस कानून को इसइल और इसके प्रधानमंत्री बेंजामीन नेतनयाह् द्वारा ऐतिहासिक निर्णय व यादगार क्षण बताया जा रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या का प्रयास करार दे रहा है। इसइली भूमि को यहूदी राष्ट्र की घोषणा के साथ ही ``हिब्रू’ को देश की राष्ट्रीय भाषा और अरबी, जिसे अधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त था, इसका अस्तित्व महज एक विशेष भाषा तक सीमित कर दिया गया है।

सतीश पेडणोकर

ससाह इसइली संसद “नेसेट” द्वारा इजरायल को अधिकारिक रूप से यहूदियों का देश घोषित करने के लिए “ज्यूज नेशन बिल” नामक कानून पारित किए जाने से एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। कानून के पारित होते ही अरबी सांसद समेत विश्व के कई मुल्कों द्वारा इसका निरंतर विरोध जारी है। कानून के क्रियान्वयन में आने से इसइल में रह रहे अन्य धर्म के लाखों निवासियों के साथ बड़े स्तर पर धार्मिक भेदभाव की आशंका चिंता का मूल कारण है। 120 सदस्यीय संसद में “यहूदी राष्ट्र बिल’ पर हुए मतदान में शामिल 62 सांसदों में 55 सांसदों की सहमति के बाद पारित इस कानून को इसइल और इसके प्रधानमंत्री बेंजामीन नेतनयाह् द्वारा ऐतिहासिक निर्णय व यादगार क्षण बताया जा रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या का प्रयास करार दे रहा है। इसइली भूमि को यहूदी राष्ट्र की घोषणा के साथ ही “हिब्रू’ को देश की राष्ट्रीय भाषा और अरबी, जिसे अधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त था, इसका अस्तित्व महज एक विशेष भाषा तक सीमित कर दिया गया है। नये कानून के तहत इसइल को यहूदियों की ऐतिहासिक मातृभूमि परिभाषित की गई है, जो सिर्फ यहूदियों को अपना फैसला स्वयं लेने का अधिकार प्रदान करता है।

कानून में यहूदी अस्तित्व के सिद्धांतों की स्थापना के साथ यहां रह रहे अन्य धर्म और उनकी पहचान को अधिकारिक रूप से नष्ट करने का प्रयास स्पष्ट है, जिससे असमानता, नस्लभेदी नीतियों और धार्मिक भेदभाव को भरपूर बढ़ावा मिलने की संभावना बनती है। नस्लीय भेदभाव और दायम दर्जे का व्यवहार अरबी नागरिकों की पुरानी शिकायत रही है। नेतनयाह् सरकार के इस फैसले से न केवल अन्य समुदाय के नागरिकों के साथ भेदभाव किया गया है बल्कि यह कानून, 1948 में इसइल की आजादी के समय घोषित सिद्धांतों का संवैधानिक वध भी है। घोषित सिद्धांतों के तहत “राष्ट्र अपने भू-भाग पर निवास कर रहे सभी नागरिकों का, चाहे वह किसी जाति, धर्म, सम्प्रदाय, मूल या लिंग का हो, के समान राजनीतिक-सामाजिक अधिकारों की रक्षा को प्रतिबद्ध है।’ अप्सोसे है कि वर्तमान सरकार अपनी 20 फीसद आबादी के सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों को तिलांजली देकर एक धर्म एजेंडे को निरंतर तूल देने में लगी हुई है।

इसइल के इस आक्रामक नीति में अविभाजित यरूशलम को अपनी राजधानी बताना, सिर्फ यहूदियों को अपना फैसला स्वयं लेने का अधिकार प्रदान करना आदि नीतियों में निश्चित तौर पर विस्तारवाद के संकेत मिलते हैं। सच है कि इजरायल में दक्षिणपंथी बेंजामीन नेतनयाह् के सत्ता में आने के बाद गैर वाजिब फैसलों ने खासकर अरबी समुदाय और अरब के मुल्कों को परेशान किया है। तथाकथित राष्ट्रवाद के तमगे के साथ नेतनयाह् एक वर्ग विशेष को दरकिनार कर

बहुसंख्यक राजनीतिक लाभ की लालच में दिनानुदिन असंवैधानिक फैसले लेते रहे हैं। बड़ा सच यह भी है कि इन प्रकरणों में इसइल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बखूबी साथ मिलता रहा है। दिसम्बर 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इसइल स्थित अमेरिकी दूतावास का तेल-अवीव से यरूशलम स्थानांतरित किए जाने की घोषणा का पूरे विश्व द्वारा कड़ा विरोध किया गया था। संयुक्त राष्ट्र समेत नित्यंतण असहमति के बावजूद अमेरिका द्वारा यरूशलम को इसइली राजधानी की मान्यता प्रदान करना चुनौती व जोखिमपूर्ण कदम रहा। फि लीस्तीनी भू-भाग पर इसइली अधिकार थोपने वाला यह कदम दशकों पुरानी इसइल-फिलीस्तीन विवाद की शांति बहाली प्रक्रिया पर बड़ा प्रहार जैसा रहा। ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस व जर्मनी समेत अरब मुल्कों द्वारा इस निर्णय की कड़ी निंदा जरूर हुई, लेकिन असर कागजों तक ही सीमित रह गया। इस स्थिति में तय स्पष्ट है कि इसइली अतिवाद में अमेरिकी सहयोग का बड़ा योगदान रहा है। ऐतिहासिक रूप से भी देखा जाए तो अमेरिका शुरू से ही इसइल को सैन्य सुविधाएं देता रहा है। 1948 में भी अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन दुनिया के पहले नेता थे, जिन्होंने इसइल को मान्यता प्रदान किया था। ऐतिहासिक यरूशलम विवाद की गंभीरता के महेनजर बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश व ओबामा आदि अमेरिकी राष्ट्रपतियों द्वारा यरूशलम पर यथास्थिति बरकरार रखी गई थी, मगर अपने चुनावी वायदों और “यहूदी प्रेम’ के कारण ट्रंप इसइल तृष्ठीकरण को प्रतिबद्ध रहे। उनके मंत्रीमंडल में यहूदीवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका भी खबरों में रही हैं। बतौर उम्मीदवार उनका चुनाव पूर्व वादा कि सत्ता में आते ही यरूशलम को बतौर इसइली राजधानी की मान्यता और इसइल समर्थन की भूमिका दोनों ही सत्य साबित हुए।मौजूदा हालात में प्रासांगिक यह



है कि फिलीस्तीनी-इसइल विवाद के केंद्र यरूशलम के मुद्दों पर एक तरफा, पक्षपातपूर्ण व सुनियोजित अमेरिकी हस्तक्षेप से नित्यंतण चिंताएं बढ़ गई हैं। इस दौरान कई अवसरों पर सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय संगठन के निर्देशों को दरकिनार कर मनमाना फैसले लिये गए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलीस्तीनी जमीं पर उपनिवेशन को लेकर पारित प्रस्ताव का इसइली नेतृत्व द्वारा ठुकराया जाना, अमेरिका द्वारा यरूशलम को बतौर राजधानी की मान्यता देना, दूतावास स्थानांतरण में तेजी के बाद अब यहूदी राष्ट्र की घोषणा आदि क्रमगत विवाद के मसले बने रहे। यह जानते हुए कि यरूशलम धार्मिक संवेदनाओं का बड़ा केंद्र है, अमेरिकी निर्णय ने अरब मुल्कों को नाराज करने का काम किया है। सात माह पूर्व इसइली प्रधानमंत्री द्वारा युद्ध संबंधी निर्णय से जुड़े सभी अधिकारों के लिए स्वयं मात्र को अधिकृत करने जैसी पहल भी सुर्खियों में थीं। इस नये कानून से पहले युद्ध संबंधी निर्णय के

अधिकारों के प्रयोग के लिए संसद की संस्तुति आवश्यक होती थी। पिछले वर्ष इसइली संसद द्वारा फिलीस्तीनी जमीं पर इसइल द्वारा बसाई गई अवैध बस्तियों को मान्यता प्रदान करने के लिए अनुमोदित नया “सेटलमेंट बिल’ भी ज्यूज नेशन स्टेट की ही एक तैयारी थी। ऐसे निर्णयों से स्पष्ट है कि यहूदी राष्ट्र की दिशा में इसइल के प्रत्येक मंसूखे में अमेरिका की सहमति और बड़-चढ़कर साथ मिलता रहा जिससे “एक राष्ट्र’ मसले पर इसइल को धरातल तैयार करने का शह मिला। मौजूदा परिदृश्य में नित्यंतण हस्तक्षेप भी गौण नजर आ रहे हैं। फिलीस्तीनी एकजुटता दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। अब संयुक्त राष्ट्र के मजबूत निष्पक्ष दखल ही शांति बहाली की एकमात्र उम्मीद है।

प्रेमचंद हिन्दी साहित्य का वह नाम

र्विवाद रूप से हिन्दी कथा साहित्य उर्दू के धनपत राय यानी हिन्दी के कथा सम्राट प्रेमचंद बिना अधूरा है। आज भी प्रेमचंद हिन्दी साहित्य का वह नाम है, जिसने केवल किस्सागोई नहीं की या मनगढंत गल्प नहीं लिखे वरन जीवन को अंदर तक छूती और झकझोरती कहानियाँ लिखी हैं। प्रेमचंद ऐसे कथाकार हैं, जिनका हर पात्र ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच का कोई जीवंत आदमी पत्रों पर उतर आया हो। होरी हो या वंशीधर, गोबर हो या धनिया अथवा शतरंज के खिलाड़ी के नवाब सारे पात्र केवल पुस्तक के पत्रों तक नहीं रहते अपितु अपने काल व वातावरण का एकदम असली रंग बिखेरते हुए रोजमर्रा के जीवन में कहीं-न-कहीं दिख जाते हैं। यह यूं ही नहीं है कि प्रेमचंद को सार्वकालिक रूसी कथाकार लियो टालस्टॉय व मैक्सिम गोर्की का मिश्रित अवतार माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद वस्तुत भारतीय हिन्दी साहित्य के ऐसे कालजयी रचनाकार हैं कि उन्हें एक तरफकरने पर हिन्दुस्तानी साहित्य अपूर्ण रह जाता है। मुंशी प्रेमचंद ऐसे “डार्क पीरियड’ में पैदा हुए, जिसमें गुलामी का दंश गहरे डस रहा था, आम भारतीय सुख की ज़िदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकता थे। अंग्रेजी शासन के तले भारतीय बुरी तरह त्रस्त थे। गरीबी व पोषण बहुत सामान्य बात थी, वर्गभेद व छुआछूत से त्रस्त भारतीय समाज घोषणा का एक आईना था और भारतीयों को उच्च शिक्षा से दूर रखने व उच्च पदों तक न पहुंचने देने का पूरा इंतजाम अंग्रेजी शासन ने कर रखा था। इन्हीं परिस्थितियों में अजायब राय व आनंदी देवी का बेटा धनपत राय अपने दूसरे भाई-बहनों के साथ बड़ा हुआ। पढ़ाई-लिखाई के प्रति उसमें बहुत रु चि न थी। परिणामतः लगातार पिछड़ते गए, यहां तक कि बारहवीं को नहीं पास कर पाए। प्रेमचंद हिन्दी साहित्य को परिस्थितियों की देन भी कहे जा सकते हैं। प्रेमचंद के सहित्य में जहां अपने समय की विसंगतियां, विद्वरूपाएं, सामाजिक असमानता, अत्याचार, विवशता, सब कुछ सह लेने की कायरता समाहित है वहीं अमीर वर्ग की अव्याशी, अस्वेदनशीलता, चाटुकारिता व अहंकार का भाव जिस सहजता से आया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। “गोदान’ के होरी झुमरू, गोबर, धनिया, “ईदगाह’ के हमीद, “नमक के दारोगा’ के वंशीधर व पं. अलोपीदीन, “पंचपरमेश्वर’ के जुम्मन व अलपू, निर्मला की निर्मला, बड़े “भाई साहब’ के बड़े भाई, “पूस की रात’ के हरखू आदि अपने युग के कालजयी प्रतिनिधि पात्र बन गए और अपने कालखंड व जीवन की पीड़ा का प्रामाणिक प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेमचंद ने हिन्दी साहित्य को अकेले दम इतना कुछ दिया है कि बाद की कई पीढ़ियां भी उतना नहीं दे पाई। अपनी लगभग हर कहानी में प्रेमचंद ने समाज को कोई-न-कोई नैतिक पाठ जरूर पढ़ाया है। साठोत्तरी कहानी के तो प्रेमचंद बादशाह हैं। आज के कुछ लेखकों के पास पैसा है, शोहरत है। छपने के लिए जुगाड़, सिफारिश व धड़े बंदियां। प्रकाशकों की चिरोरी करना अब छिपा नहीं है। प्रकाशक भी अधिककर, अनपके लेखकों की छपने की लिप्सा को पूरी तरह दुह रहे हैं। अपने पैसे से चंद प्रतियां छपवाने वाले और बंटवाने वाले विमोचन समारोही लेखकों के अलावा सोशल मीडिया व वेब पेजों तक सीमित रहने वाले कुकुरमुत्तों टाइप लेखकों के बीच क्यों दूसरा प्रेमचंद पैदा नहीं हुआ, इस बात पर प्रेमचंद की जयंती पर चिंतन-मनन करने की महती आवश्यकता है। हम अपने समय में भी कुछ ऐसे प्रेमचंद तराशें व तलाशें जो समकालीन भारतीय जीवन को वांछित मूल्य प्रदान करने वाले साहित्य का सृजन कर प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ा सकें।

चलते चलते

वारंट को “तामील किया गया’

भारतीयों को लेकर इनके स्थानीय परिवेश के लोगों में गंजब की चमक होती है। यही चमक उन्हें उनसे वैवाहिक संबंध जोड़ने के लिए भी आकर्षित करती है। मगर हाल के सालों में यह चमक तकलीफ देह यादगारी में बदल गई है।

धोखेबाज पति की शिकार हुई। अधिकारिक आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए इस बात को भी संज्ञान में रखने की जरूरत है कि भारतीय समाज विवाह को निजी मसला मानता है। इसलिए वैवाहिक विवाद परिवार-समाज की चौहद्दी में ही रहते हैं। जाहिर तौर पर ये आंकड़े ज्यादा ही होंगे। अब सरकार इन धोखेबाज दूल्हों पर वॉक कसने के लिए प्रभावी कानूनी तरीके अपनाने जा रही है। इसके तहत उनकी सम्पति को जब्त करने से लेकर उन्हें वांछित अपराधी घोषित किया जाएगा। शीतकालीन सत्र में आ रहे कानून में शादियों का पंजीकरण एक सप्ताह के भीतर

फोटोग्राफी...



एनुअल हॉर्स बग्घी रेस...जर्मनी के शहर कक्सहेवेन में एनुअल हॉर्स बग्घी रेस के दौरानद् आया

युड़सवार। यह रेस 1902 से होती आ रही है और तभी होती है जब समुद्र में हल्की लहरें उठ रही हो।



सूरत । गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राज्य सभा में सम्राट चन्द्र गुप्त मौर्य के विषय में विवादित बयान के खिलाफ सोमवार को डिंडोली से कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा ।

अलग अलग जोन में कुल ९९ युनिट सीट हुए गंदगी फैलाने वाले युनिटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

अहमदाबाद । अहमदाबाद शहर के म्युनिसिपल कमिशनर विजय नेहरेा के आदेश के अनुसार सार्वजनिक जगहों पर गंदगी करने वाले वाणिज्य युनिटों के खिलाफ तंत्र की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा रही है । शहर के अलग अलग इलाकों में सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है । आज अहमदाबाद शहर में कॉर्पोरेशन की ओर से आक्रमक कार्रवाई की गई । जिसके चलते १०० से अधिक युनिटों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया गया । शहर के मोटेरा इलाके में स्थित डीमार्ट भी शामिल है । कॉर्पोरेशन की ओर से इस अभियान में अबतक शहरभर में ६६१ से अधिक युनिट को सील किये जा चुके हैं । अगले दिनों में भी कार्रवाई जारी रहने की संभावना है । गंदगी फैलाने वाले युनिटों के खिलाफ कार्रवाई और अधिक कड़ी की जाएगी । आज शहर के पश्चिम जोन के साबरमती बोर्ड के स्मृति मंदिर के निकट मोडर्न ऐरा, रामनगर

कहा कितने युनिट सील

अहमदाबाद, ३० जुलाई ।	
अहमदाबाद शहर में अलग अलग इलाकों में कहा कितने युनिट सील हुए यह निम्न है ।	
तारीख.....	सील युनिट की संख्या
२६-०७-२०१८.....	८९
२७-०७-२०१८.....	२१४
२८-०७-२०१८.....	२५९
३०-०७-२०१८.....	९९
कुल.....	६६१

में प्रकाश कोलडिन्क, आयुषी नास्ता हाउस, बेरोनेट कोम्पलेक्स चार रास्ता के निकट सत्यम पान पार्लर, जवाहर चोक में चामुंडा पान पार्लर, चांदखेडा बोर्ड में आईओसी-चांदखेडा रोड पर मिलन चवाणा एन्ड स्वीटमार्ट, हरसिद्ध स्टेशनरी मार्ट, चांदखेडा बस स्टेशन के निकट बजरंग पान पार्लर, प्रकाश पान पार्लर, न्यु सीजी रोड पर लक्ष्मी विजेटेबल मार्ट के खिलाफ साबर्वजनिक रूप से गंदगी फैलाने के कारण सीलिंग की गई है । जिसके चलते व्यापारियों में भी भारी देहशत फैल गई है । दुसरी और चांदखेडा में उत्तम स्वीटमार्ट के शुभारंभ खुलाजी चौधरी के

अहमदाबाद में उल्टी-दस्त के २८ दिन में ९६७ केस

अहमदाबाद । मोनसून की सिजन चल रही है तब अहमदाबाद शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से मच्छरजनीत और पानीजनीत रोगों को रोकने के लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं फिर भी शहर के अलग अलग जोन में मच्छरजनीत और जलजनीत केस सतह पर आ रहे हैं ।



अहमदाबाद में ऑटोरिक्सा चालकों की हड़ताल के चलते शहर के एएमटीएस बस स्टेन्ड पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली ।

सीजी रोड पर घंटे के अनुसार पार्किंग चार्ज वसूला जाएगा

अहमदाबाद । एएमसी प्रशासन द्वारा अब शहर के सीजी

रोड पर घंटे के अनुसार पार्किंग चार्ज वसूलने की कवायद शुरू की गई

है । भाजपा के शासकों ने शहर के सीजी. रोड पर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वाहन पार्क कर सकें इस उद्देश्य से संबंधित वाहन के पार्किंग चार्जिस घंटे के अनुसार वसूलने की दिशा में काम शुरू किया गया है । फिलहाल में शहरभर में विशेष करके ट्राफिक के मुद्दे पर गुजरात हाईकोर्ट के आदेश की वजह से ट्राफिक पुलिस और म्युनिसिपल प्रशासन सक्रिय हो गया है । ट्राफिक पुलिस द्वारा ट्राफिक नियम के लिए सख्ती से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है । दूसरी तरफ एएमसी प्रशासन भी ६५ से ज्यादा ट्राफिक जंक्शन पर अतिक्रमण हटाने की दिशा में विशेष कार्रवाई की गई है । इसके अलावा शहरीजनों को ज्यादा से ज्यादा पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नये २५ पार्किंग प्लोट में पार्किंग की सुविधा देने की दिशा में कवायद शुरू की गई है ।

गुजरात हाईकोर्ट ने अति महत्वपूर्ण फैसला सुनाया

अब आरटीई के तहत सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाए

अल्पसंख्यक समाज के लोगों की ओर से चलाई जाने वाली स्कुलो के लिए भी हाईकोर्ट का हुकम जारी

अहमदाबाद । गुजरात में समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को राइट टु एजुकेशन (आरटीई) एक्ट के तहत बिना मूल्य प्रवेश के बारे में की गई रीट अर्जी पर गुजरात हाईकोर्ट ने आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया । हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरटीई के तहत संबंधित सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाए । हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों की ओर से चलाई जाने वाली अल्पसंख्यक शैक्षणिक ट्रस्ट का स्टेटस ऐसे ही नहीं मिल जाता है । हाईकोर्ट के जस्टीस एम.आर. शाह और जस्टीस ए.वाय. कोकजे की खंडपीठ ने आरटीई

एक्ट के तहत की गई अर्जीयों पर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण बातें भी बताईं । संबंधित सभी बच्चों के प्रवेश देने के लिए राज्य सरकार को आदेश किया गया है । जिन बच्चों के प्रवेश को लेकर अर्जी की गई होगी उन सभी को प्रवेश देने के लिए हाईकोर्ट में सरकार से स्पष्ट आदेश किए हैं । सामाजिक कार्यकर चंद्रवदन ध्रुव की ओर से की गई अर्जी के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है । हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि टेकनिकल कारणोंपर जो याचिकाएं रद्द की जा चुकी हैं उन्हें फिरसे मौका दिया जाएगा और प्रथम राउन्ड के बाद बाकी रहे गए सभी बच्चों को आरटीई के तहत

स्कुलो में प्रवेश दिया जाएगा । हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अल्पसंख्यक स्कुलो और उनके स्टेटस को लेकर भी महत्वपूर्ण आदेश किया । हाईकोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली अल्पसंख्यक शैक्षणिक ट्रस्ट का स्टेटस ऐसे ही नहीं मिल जाता है । जो स्कुले संस्थाएं, ट्रस्ट अल्पसंख्यक के रूप में जरूरी मान्यता रखते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आरटीई के दायरे से बाहर रखा जाता है किन्तु जिनके पास कोई मान्यता नहीं है उन्हें आरटीई की तहत २५ फीसदी के अनुसार बच्चों को कक्षा-१ में फ्री में प्रवेश दिया जाए । हाईकोर्ट के इस

आदेश से अल्पसंख्यक स्कुलो और ट्रस्टों को भी बड़ा झटका लगा है । इन संस्थाओं ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम में जाने के लिए दो सप्ताह के लिए स्टे की मांग की थी । हाईकोर्ट ने मांग के बाद १४ अगस्त तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाने की मंजूरी दे दी है । चंद्रवदन ध्रुव ने बताया कि जीन स्कुलों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं मिली है फिर भी उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है । कानूनी प्रक्रिया के चलते राज्य के ४५ हजार से अधिक बच्चों को प्रवेश एक में प्रवेश देने में विलंब हुआ है । राज्य में ५३४९० बच्चों को प्रवेश से वंचित रखा गया है ।

आज २१ चतुर्थी का फल देने वाली अंगारकी संकष्टी चतुर्थी

लालदरवाजा के सिद्धिविनायक, गणपतिपुरा के प्रसिद्ध गणपतिमंदिर सहित के मंदिरों में भक्तों की लंबी लाइन

अहमदाबाद । हरएक शुभ कार्य की शुरुआत जिनके स्मरण से होता है ऐसे विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ दिन यानी कि अंगारकी संकष्टी चतुर्थी मंगलवार और अंगारकी चतुर्थी का अनोखा संयोग बन गया है, जिसे लेकर गणेशभक्तों में भारी उत्साह और भक्ति का माहौल छाया हुआ है । मंगलवार की अंगारकी चतुर्थी २१ चतुर्थी का फल देनेवाली होने की वजह से गणेश भगवान की कृपा और आशीर्वाद लेने के लिए मंगलवार को अहमदाबाद शहर सहित राज्यभर के गणेशमंदिरों में गणेशभक्तों की लाइन लग जाएगी । ज्योतिषियों के अनुसार मंगलवार रात को ९.४० बजे चंद्रोदय होगा जिसकी वजह से मंदिर के दरवाजे तब तक खुले रहेंगे । शहर के लालदरवाजा में सिद्धिविनायक मंदिर, धोलका तहसील के कोठगांव में गणपतिपुरा के प्रसिद्ध गणपतिमंदिर, महेमदावाद के सिद्धिविनायक, वस्त्रापुर के गणपति मंदिर, शाहीबाग के गणेश मंदिर सहित राज्यभर के गणेश मंदिरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के

दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे तब मंदिर प्रशासन द्वारा भी मंगलवार की अंगारकी चतुर्थी को लेकर भक्तों के लिए दर्शन की विशेष व्यवस्था और प्रसाद की तैयारियां की गई हैं । गणेश भक्तों में अंगारकी संकष्टी चतुर्थी का काफी महत्व है । शास्त्रों के अनुसार यह एक चतुर्थी करने से २१ चतुर्थी करने का फल प्राप्त होता है । मंगलवार को विक्रम संवत् २०७४ की तीसरी और अंतिम अंगारकी संकष्टी चतुर्थी है । अब आगामी अंगारकी संकष्टी चतुर्थी विक्रम संवत् २०७५ के महीने में २५ दिसम्बर को आयेगा । अंगारकी संकष्टी चतुर्थी गणेश भगवान की साधना -प्रार्थना करने का और उनकी कृपा प्राप्त करने का अनोखा दिन है ।

विघ्नहर्ता भगवान लाखों भक्त अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करके प्रार्थना-पूजा के साथ भगवान गणेश को प्रसन्न करने का मनाने का प्रयास करते हैं । यह दिन गणेश पूजा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण दिन होता है । शास्त्र के विशेषज्ञों द्वारा बताये अनुसार इस दिन में संभव हो सके उतनी बार ओम् गं गणपतयै नमः का पाठ करना चाहिए ।

किसी भी हालात में शहर में हुए गड़्हे का तुरंत समाधान करे

अहमदाबाद । अहमदाबाद शहर में खराब रास्तों, आवारा पशुओं की स्थिति और मॉनसून के दौरान हुए गड़्हे की परिस्थिति को लेकर चल रहे केस की सुनवाई के दौरान सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट ने शहर में हुए गड़्हे को लेकर तुरंत एएमसी प्रशासन द्वारा शुरू किए गए कामकाज को लेकर भारी नाराजगी व्यक्त की गई है । जस्टिस एमआर. शाह और जस्टिस एवाय. कोगजे की खंडपीठ ने एएमसी प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा है कि, शहर में विभिन्न क्षेत्रों में हुए गड़्हे के कारण शहर में भयंकर और खतरनाक परिस्थिति का निर्माण हुआ है ।



शहर के सरदारनगर पुलिस स्टेशन इलाके में एडवोकेट पर हमला होने के बाद इस घटना के विरोध में सिटी मेट्रो कोर्ट में एडवोकेट ने कोर्ट कार्रवाई का बहिष्कार किया ।

जोधपुर में सीएम आवास योजना की अपार्टमेन्ट की दीवार धराशायी

अहमदाबाद । शहर के जोधपुर क्षेत्र में स्थित मुख्यमंत्री आवास योजना के सोमेश्वर अपार्टमेन्ट की बड़ी दीवार सोमवार को सुबह में पास में चल रहे कन्स्ट्रक्शन साइट के लिए खोदे गये गहरे गड़्हे में गिर गई थी । सोमेश्वर अपार्टमेन्ट के निवासी की एक कार दीवार के पास पार्क की थी । दीवार धराशायी होने पर कार भी गहरे खाई में गिर गई थी । दीवार धराशायी होने पर कोई हताहत नहीं हुआ है । लेकिन जेसीबी, ट्रैक्टर और कार को नुकसान पहुंचा है । इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार, सोमेश्वर अपार्टमेन्ट से सटे पेलेडियम अपार्टमेन्ट का निर्माणकाम हो रहा है, जिसकी वजह से यह दीवाल धराशायी होने का स्थानीय निवासी मान रहे हैं । सुबह में हुई इस घटना में हताहत टल गया है, क्योंकि पेलेडियम अपार्टमेन्ट में कई मजदूर काम करते हैं । सुबह के नौ बजे के बाद सभी मजदूर काम पर आ जाते हैं तब यह घटना के सुबह में ८ बजे हुई थी । हालांकि कोई हताहत नहीं होने पर स्थानीय निवासियों ने राहत महसूस की है । जोधपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास योजना की सोमेश्वर अपार्टमेन्ट की करीब १०० फीट से ज्यादा की दीवार धराशायी हो गई थी । सोमेश्वर अपार्टमेन्ट के पास में पेलेडियम अपार्टमेन्ट नाम के फ्लैट बन रहे हैं । यह फ्लैट का नींव खुदाई किया गया है और कितना निर्माणकाम हो गया है । पेलेडियम अपार्टमेन्ट के लिए सोमेश्वर अपार्टमेन्ट की दीवार से सटे नींव खोदा गया है, जिसके कारण दीवार गिर जाए ऐसी स्थिति में थी ।

महादेव मीडिया

रोहताश यादव 9924144499, 7015339195

वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)

हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाइन करवाने के लिए संपर्क करें।

304 केवल कॉम्पलेक्स नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।